



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122020-223744
CG-DL-E-17122020-223744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2020/ अग्रहायण 26, 1942

No. 356]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

मामला सं. ए डी (ओआई) 30/2020

विषय : जापान, ईरान, कतर तथा ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/36/2020-डीजीटीआर.—1. मै. अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उत्पादकों अर्थात्, डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज तथा कैमिकल्स लिमिटेड, एस आई ई एल कैमिकल कॉम्पलैक्स की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे आगे याचिका या आवेदन भी कहा गया है) दायर किया है जिसमें जापान, ईरान, ओमान तथा कतर (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। घरेलू उत्पादक अर्थात् डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज तथा कैमिकल्स लिमिटेड, एस आई ई एल कैमिकल कॉम्पलैक्स (जिन्हें आगे भागीदार कंपनियां भी कहा गया है) ने आवेदन में विहित सूचना उपलब्ध कराई है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि जापान, ईरान, कतर तथा ओमान से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने जापान, ईरान, कतर तथा ओमान से कॉस्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'कॉस्टिक सोडा' या सभी रूपों में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉस्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच या सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। यह एक साबुन जैसा, अत्यधिक अल्कलाइन, गंधहीन, तरल होता है जिसका अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में कच्ची सामग्री या सहायक रसायन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कॉस्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों लाई और ठोस में किया जाता है। ठोस रूप फ्लेक्स, प्रिल्स, ग्रेन्युअल्स या किसी अन्य रूप में हो सकता है।
4. कॉस्टिक सोडा 3 प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डाईफैग्राम प्रक्रिया और मैम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात् लाई और ठोस में उत्पादित किया जाता है तरल रूप को ठोस रूप में बदला जा सकता है और ठोस रूप को आसानी से पुनः तरल रूप में बदला जा सकता है तथा इससे उत्पाद की रासायनिक विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठोस रूप के भंडारण और परिवहन में सरलता रहती है जबकि तरल रूप आसानी से घुलता है। अंतिम प्रयोग हेतु दोनों रूप प्रतिस्थापनीय और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग योग्य हैं।
5. कॉस्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के तहत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के अधीन अध्याय-28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आईटी सी8 अंकीय वर्गीकरण के अनुसार इस उत्पाद को सामाशुल्क शीर्ष 28151101, 28151102 और 28151200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ख. समान वस्तु

6. "समान वस्तु" से संबंधित नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है :
- "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*
7. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। संबद्ध वस्तुएं आयातित संबद्ध वस्तु से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता संबद्ध वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), द्वारा दायर किया गया है। डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज तथा कैमिकल्स लिमिटेड, एस आई ई एल कैमिकल कॉम्पलैक्स और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (जिन्हें यहां आगे "प्रतिभागी कंपनियां" भी कहा गया है) ने क्षति संबंधी सूचना दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भागीदार कंपनियों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। भागीदार कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और इन भागीदार कंपनियों ने क्षति संबंधी संगत सूचना दी है।
9. इसके अलावा संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों ने आवेदकों का समर्थन किया है अर्थात्, i. कैमफैब एल्कलीज लिमिटेड, ii. कैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, iii. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, iv. गुजरात प्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड, v. लॉर्डस क्लोरो एल्कली लिमिटेड, vi. मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड, vii. निरमा लिमिटेड, viii. ओरिएंट पेपर

मिल्स, ix. पंजाब एल्कलीज एंड एंड कैमिकल्स लिमिटेड, x. तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, xi. टाटा कैमिकल्स लिमिटेड, xii. टीजीवी एसआरएएसी लिमिटेड, xiii. दि आंध्रा शुगर्स लिमिटेड, xiv. दि ट्रेवनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड।

10. यह नोट किया जाता है कि समर्थकों के साथ भागीदार कंपनियों का कुल भारतीय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है। उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि भागीदार कंपनियों नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

जापान के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए आवेदक ने बाजार शोध एजेंसी आईएच एस मार्केट द्वारा उसके आवधिक प्रकाशन ग्लोबल क्लोर एल्कली रिपोर्ट में दी गई कीमत को जापान के आयातों हेतु अपनाया है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु उस कीमत पर विचार किया है।

ईरान के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास ईरान में घरेलू बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार आवेदक ने समुचित तीसरे देश अर्थात् जॉर्जिया को निर्यातों की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ट्रेड मैप डेटा के जरिए अपनाया है, इसमें यह माना गया है कि जॉर्जिया को निर्यात ईरान से जॉर्जिया को निर्यातों की सर्वाधिक मात्रा दर्शाते हैं। इसके अलावा आवेदक ने कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किया है। ईरान के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ओमान के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास ओमान में घरेलू बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार आवेदक ने समुचित तीसरे देश अर्थात् यूएई को निर्यातों की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ट्रेड मैप डेटा के जरिए अपनाया है, इसमें यह माना गया है कि यूएई को निर्यातों की मात्रा ओमान से यूएई को निर्यातों की सर्वाधिक मात्रा दर्शाते हैं। इसके अलावा आवेदक ने कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किया है। ओमान के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

कतर के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास कतर में घरेलू बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार आवेदक ने समुचित तीसरे देश अर्थात् इटली को निर्यातों की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ट्रेड मैप डेटा के जरिए अपनाया है, इसमें यह माना गया है कि इटली को निर्यातों की मात्रा कतर से इटली को निर्यातों की सर्वाधिक मात्रा दर्शाते हैं। इसके अलावा आवेदक ने कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किया है। कतर के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ख. निर्यात कीमत

15. संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार कमीशन, ऋण लागत और संभलाई प्रभार के लिए समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों के लिए दावा की गई निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

क. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे जापान, ईरान, कतर और ओमान से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने और अत्यधिक होने का प्रथमदृष्टया पता चलता है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि जापान, ईरान, कतर और ओमान से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति, परिणामी कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उत्पादन, बिक्री, मालसूची और लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में गिरावट के संबंध में उनका कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच में संबद्ध देश जापान, ईरान, कतर तथा ओमान हैं।

जांच की अवधि

20. आवेदक ने अक्टूबर, 2019 से जून, 2020 (9 महीने) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है तथा 2016-17, 2017-18, अप्रैल, 2018-सितंबर, 2019 तथा जांच की अवधि को क्षति जांच अवधि के रूप में माना है। तथापि, प्राधिकारी नियम 2(घक) और नियम 22 के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की अवधि को जांच अवधि (पीओआई) के रूप में और 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019- 31 मार्च, 2020 और जांच अवधि (पी ओ आई) अर्थात् 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 को क्षति अवधि के रूप में नियत करना उचित समझते हैं।

प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ईमेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December 2020

Case No. AD (OI)-30/2020

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Caustic Soda originating in or exported from Japan, Iran, Qatar and Oman.

F. No. 6/36/2020-DGTR.—M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application (hereinafter also referred to as the “Petition” or “Application”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, DCW Limited, Grasim Industries Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, SIEL Chemical Complex in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), for imposition of Anti-Dumping duty on imports of Caustic Soda originating in or exported from Japan, Iran, Oman and Qatar (hereinafter also referred to as the “subject countries”). The domestic producers namely, DCW Limited, Grasim Industries Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, SIEL Chemical Complex (hereinafter referred to as “Participating Companies”) have provided the prescribed information in the Application.

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic industry is being caused due to dumped imports from Japan, Iran, Qatar and Oman, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of Caustic Soda from Japan, Iran, Qatar and Oman.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

3. The product under consideration in the petition is Caustic Soda or Sodium Hydroxide, in all forms. Caustic Soda is chemically known as NaOH or Sodium Hydroxide. It is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic Soda is produced in two forms, lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form.

4. Caustic Soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable.
5. Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC 8-digit classification, the product is classified under the Custom Heading 28151101, 28151102 and 28151200. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration

LIKE ARTICLE

6. Rule 2(d) with regard to “like article” provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

7. The Applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and product under consideration exported from subject countries. Subject goods produced by the domestic producers and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The subject goods are technically and commercially substitutable with imported subject goods. The consumers are using the subject goods interchangeably. Therefore, subject goods produced by the domestic producers are being treated as “like article” to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

8. The application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI). DCW Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, SEIL Chemical Complex and Grasim Industries Limited (also referred to as “participating companies”) have provided injury information. As per the available information, the “participating companies” have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India. The production of the participating companies constitutes a major proportion in Indian production, and these participating companies have provided relevant injury information.
9. Further, the application is supported by the following producers of the subject goods i.e. Chemfab Alkalies Limited, Chemplast Sanmar Limited, DCM Shriram Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Lords Chloro Alkali Limited, Meghmani Finechem Limited, Nirma Limited, Orient Paper Mills, Punjab Alkalies & Chemicals Limited, Tamilnadu Petroproducts Limited, Tata Chemicals Limited, TGV SRAAC Limited, The Andhra Sugars Limited, The Travancore-Cochin Chemicals Limited, Chemfab Alkalies Limited, Chemplast Sanmar Limited, DCM Shriram Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Lords Chloro Alkali Limited, Meghmani Finechem Limited, Nirma Limited, Orient Paper Mills, Punjab Alkalies & Chemicals Limited, Tamilnadu Petroproducts Limited, Tata Chemicals Limited, TGV SRAAC Limited, The Andhra Sugars Limited, The Travancore-Cochin Chemicals Limited
10. It is noted that the participating companies, along with the supporters, account for more than 50% of the total domestic production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the participating companies constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

BASIS OF ALLEGED DUMPING**Normal value****Normal value for Japan**

11. The Applicant has claimed that there was no evidence of domestic selling price in the subject country, so, the Applicant has adopted the price published by the market research agency, IHS Markit, in its periodic publication Global Chlor-Alkali Report, for imports from Japan. Accordingly, the Applicant has considered such prices for determining the normal value for the subject country.

Normal value for Iran

12. The Applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price in Iran. Thus, the Applicant has adopted price of exports to an appropriate third country, i.e., Georgia, derived through Trade Map data for the determination of normal value, considering that volume of exports to Georgia represents highest volume of exports from Iran to Georgia. Further, the Applicant has adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses and inland freight to determine ex-factory normal value. There is sufficient prima facie evidence of normal value claimed for Iran.

Normal value for Oman

13. The Applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price in Oman. Thus, the Applicant has adopted price of exports to an appropriate third country, UAE, derived through Trade Map data for the determination of normal value, considering that volume of exports to UAE represents highest volume of exports from Oman to UAE. Further, the Applicant has adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses and inland freight to determine ex-factory normal value. There is sufficient prima facie evidence of normal value claimed for Oman.

Normal value for Qatar

14. The Applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price in Qatar. Thus, the Applicant has adopted price of exports to an appropriate third country, Italy, derived through Trade Map data for the determination of normal value, considering that volume of exports to Italy represents highest volume of exports from Qatar to Italy. Further, the Applicant has adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses and inland freight to determine ex-factory normal value. There is sufficient prima facie evidence of normal value claimed for Qatar.

Export Price

15. The export price for the subject countries has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and handling charges. There is sufficient evidence of export prices claimed for subject countries.

a. Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from Japan, Iran, Qatar and Oman. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from Japan, Iran, Qatar and Oman.

INJURY AND CAUSAL LINK

17. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in price undercutting, and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that their performance has been adversely impacted in respect of production, sales, inventories and decline in profits, return on capital employed, and cash profits. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of anti-dumping investigation.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry

SUBJECT COUNTRIES

19. The subject countries in the present investigation are Japan, Iran, Qatar and Oman.

PERIOD OF INVESTIGATION

20. The Applicant has proposed period of investigation (POI) as October 2019 to June 2020 (9 months), with the injury investigation period as 2016-17, 2017-18, April 2018 – September 2019 and the period of investigation. The Authority however considers it appropriate, having regard to Rule 2(da), and explanation to rule 22, to fix the period 1st October 2019 to 30th September 2020, as period of investigation (POI) and the period 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, and the period of investigation (POI) i.e. 1st October 2019 to 30th September, 2020 as the injury investigation period.

PROCEDURE

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation

SUBMISSION OF INFORMATION

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation

TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
31. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority